CPI(M)

जन जोहार झारखण्ड

अंक–02 | मासिक बुलेटिन | जुलाई 2022

संपादकीय ....

जन जोहार डिजिटल बुलेटिन का दुसरा अंक एतेहासिक हूल दिवस के मौके पर आपके सामने है। हमने झारखंड में आदिवासी उलगुलान के नायक बिरसा मुंडा के शहीदी दिवस पर इसका पहला अंक जारी किया था। इस छोटी सी अवधि में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और हमारे राज्य झारखंड में अनेक घटनाएं सामने आई हैं।

लैटिन अमेरिकी देश कोलंबिया में पहली बार वामपक्ष के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का भारी बहुमत से चुना जाना एक बड़ी राजनीतिक घटना है। यह साम्राज्यवाद की दादागिरी के खिलाफ जनादेश है। यह जीत केवल उस देश में जारी असंतोष का परिणाम नहीं बल्कि यह कोलंबिया के मेहनतकशों द्वारा पिछले दिनों किए गए शानदार संघर्षों का नतीजा है। लैटिन अमेरिकी देश अपने अनुभवों से सीख कर वामपक्षीय दिशा की राह अपना रहें हैं जो मेहनतकशों की अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को आने वाले दिनों में और मजबूत करेगा।

राष्ट्रीय परिदृश्य मे आरएसएस के निर्देशन में शासक पार्टी भाजपा द्वारा चलाए जा रहे सुनियोजित धार्मिक उन्माद की राजनीति के चलते मोदी सरकार को मुस्लिम देशों की कड़ी कूटनीतिक प्रतिक्रिया को झेलना पड़ रहा है क्योंकि भाजपा के हिंदुत्ववादी सांप्रदायिक हथकंडों का एजेंडा अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के घेरे में है और दुनिया की नजरें स्वघोषित विश्वगुरु के कालिख पूते मक्कार चेहरे पर पड़ रही है इसलिए मोदी सरकार इस तूफान के निकल जाने का इंतजार कर रही है, ताकि अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ नफ़रत की मुहिम जारी रख सके। संसद के आगामी मानसून सेशन में भाजपा उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम 1991 के प्रावधानों को निरस्त करने के लिए एक गैर सरकारी विधेयक पेश किए जाने के लिए राज्यसभा सचिवालय को नोटिस दे

शेष पृष्ठ 3 पर .....

भारत का प्रथम जनयुद्ध ... हूल जारी रहे

ईस्ट इंडिया कम्पनी के खिलाफ़ प्रथम विद्रोह सन् 1784 में तिलका माँझी के नेतृत्व में हुआ था। इसके 71 वर्ष बाद का 'संताल हूल' वास्तव में संतालों द्वारा अपनी जमीन जिसे उन्होंने अपनी सामुहिक मेहनत से खेती के लायक तैयार किया था, उसे बचाए रखने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सशस्त्र जनयुद्ध था। मार्क्स ने संताल हूल को 'भारत की प्रथम जनक्रांति' कहा था।

स्थाई बंदोबस्ती के साथ ईस्ट इंडिया कम्पनी ने संतालों की भी भूमि अधिकारों की व्यवस्था को बदल दिया जो संताल मुग़लों को भी लगान नहीं देते थे, उनपर ज़मीन–क़ब्ज़े की नीयत से मालगुज़ारी लाद दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके समर्थकों, जमींदारों, महाजनों, साहुकारों और उनकी पुलिस आदि के द्वारा लूट–पाट, शोषण, बलात्कार जैसे उत्पीड़न व जुल्म से संताल त्रस्त थे, लेकिन उनकी अधीनता उन्हें स्वीकार नहीं थी। वैसी परिस्थिति में सिदो–कान्हू ने संताल गांवों में डुगडुगी बजवा कर 400 गांवों को न्योता दिया। 30 जून, 1855 को 400 गांवों के करीब 50 हजार आदिवासी भोगनाडीह गांव पहुंचे जहां उनकी एक विशाल जनसभा हुई और इसी सभा में यह घोषणा कर दी गई कि वे अब मालगुजारी नहीं देंगे। यहीं से अंग्रेजी कंपनी और उसके समर्थकों के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ जो जनयुद्ध में बदल गया। यह जनयुद्ध एक संगठित युद्ध था, जिसमें उस वक्त के समाज के तमाम शोषित समूहों ने सक्रिय योगदान दिया था, जिनमें मंगरा पुजहर (पहाड़िया), गोरेया पुजहर (पहाड़िया), हरदास जमादार (ओबीसी), ठाकुर दास (दलित), बेचु अहीर (ओबीसी) को फाँसी दी गई और गंदू लोहरा, चुकू डोम (दलित), मानसिंग (ओबीसी) और गुरुचरण दास (दलित) को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। उल्लेखनीय है कि इस इलाके के सवर्णो को छोड़कर पिछड़े व दलित वर्ग के लोगों के साथ कपड़े बुनने वाले मुस्लिम जुलाहे, पशु पालक ग्वाला और लोहार जैसे परंपरागत दक्ष कारीगर भी बहुत बड़ी संख्या में इस हूल में शामिल थे।

ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिदो, कान्हू, चांद तथा भैरव– चारों भाइयों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। जिस दरोगा को चारों भाइयों को गिरफ्तार करने के लिए वहां भेजा गया था, संतालों ने उसकी गर्दन काट कर हत्या

शेष पृष्ठ 3 पर .....

मातृ उद्योग एचईसी को बेचने की साजिश

एचईसी इस्पात, खनन, रेलवे, ऊर्जा, रक्षा, अंतरिक्ष अनुसंधान, परमाणु और सामरिक क्षेत्रों के लिए उपकरणों का निर्माण करता रहा है। लगभग 2800 हेक्टेयर में चल रही कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1958 को हुई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 नवंबर 1963 को इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। उस वक्त इसे 'मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्री' कहा गया और आज इसी मदर ऑफ इंडस्ट्री (एचईसी) पर संकट के गहरे बादल हैं।

एचईसी ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं जिनमें 1971 के युद्ध में इंडियन माउंटेन टैंक, 105 एमएम गैन बैरल, टी–72 टैंक की कास्टिंग, 120 एमएम गन का हीट ट्रीटमेंट और मशीनिंग, आईएनएस राणा के लिए गियर सिस्टम का निर्माण, युद्धपोतों के लिए आर्मर प्लेट का निर्माण, आधुनिक रडार, परमाणु पनडुब्बी, चंद्रयान–जीएसएलवी के लिए लॉन्च पैड के महत्वपूर्ण उपकरणों का निर्माण किया है। तेजी से फैलते औद्योगिकरण के दौर में एचईसी की प्रासंगिकता और उपयोगिता और बढ़ गई है।

निजीकरण और विनिवेशीकरण में लगी कॉरपोरेटपरस्त केंद्र सरकार देश की औद्योगिक क्रांति की बुनियाद इस सार्वजनिक उपक्रम को ख़त्म करने पर अमादा है। 2000 करोड़ रू॰ के ऑर्डर और 1200 करोड़ रू॰ के फ़ाइनल ऑर्डर के बावजूद वर्किंग कैपिटल नहीं होने के चलते कंपनी बेबस है। स्पष्ट है कि सरकार की मंशा एचईसी को बंद करने की है या पूरी तरह से रुग्ण कर के औने–पौने दाम में अडानी जैसों को बेचने की है। वरना क्या कारण हो सकता है कि 60 साल पुराने इस स्वर्णिम मातृ उद्योग का नीति आयोग तक द्वारा स्वीकृती मिलने के बावजूद आधुनिकीकरण ना हो, वर्किंग कैपिटल न मिले, बैंक गारंटी कैन्सल हो जाए, 1100 एकड़ उपयोगी ज़मीन के बावजूद लोन तक मुहैया न कराया जाय, कर्मचारियों को दस महीने से वेतन ना मिले, सैकड़ों क्वार्टर बर्बाद हो रहे हों या अवैध रूप से क़ब्ज़ा कर लिए गए हों। और तो और 2019 से एचईसी में स्थाई

शेष पृष्ठ 4 पर .....

'अग्निपथ' रद्द करो

14 जून को तीनों सेनाध्यक्षों की उपस्थिति में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने "अग्निपथ भर्ती स्कीम" की घोषणा की। अब सेना में बहाली की पुरानी प्रणाली ख़त्म कर सारी बहाली 'अग्निपथ भर्ती स्कीम' से की जाएगी। अग्निपथ योजना ने देश–सेवा में मर–मिटने की भावना से ओत–प्रोत लाखों नौजवानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ये बहालियाँ चार वर्षों के लिए होगी, जिसमें छः मास का प्रशिक्षण होगा। देश की वित्तीय व्यवस्था पर बोझ कम करने के लिए उन्हें कम वेतन और बिना पेन्शन के नियुक्त किया जाएगा। चार साल के बाद उनमें से सिर्फ़ 25 प्रतिशत को सेना में आगे नियुक्ति का आश्वासन है, शेष 75 प्रतिशत को अर्धसैनिक बलों, पुलिस, कोरपोरेट्स की नौकरी में 10% प्राथमिकता दी जाएगी। ज्ञात हो कि रिटायर्ड जवानों के लिए 10% प्राथमिकता का प्रावधान पहले से ही है

शेष पृष्ठ 3 पर .....

खरीफ एमएसपी ... किसानों से फिर धोखाधड़ी

अखिल भारतीय किसान सभा ने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में मामूली बढ़ोतरी को मोदी सरकार की किसानों के साथ धोखाधड़ी बताया है। किसान सभा ने कहा है कि खरीफ 2022–23 के लिए घोषित एमएसपी में चावल, मक्का, अरहर, उड़द और मूंगफली के लिए एमएसपी में सिर्फ 7 फीसदी और बाजरा के लिए सिर्फ 8 फीसदी की बढ़ोतरी की गयी है। अधिकांश फसलों में यह वृद्धि अर्थव्यवस्था में सामान्य मुद्रास्फीति को मुश्किल से ही कवर करती है।

ये वृद्धि भी तब की गयी है जब जब ईंधन और अन्य आदानों की उच्च कीमतों और उर्वरकों की आपूर्ति में भारी कमी और कीमतों में वृद्धि के कारण उत्पादन लागत में तेजी से वृद्धि हुई है।

पिछले सीजन में भी, आपूर्ति की कमी के कारण किसानों को उर्वरकों की कालाबाजारी का बड़े पैमाने पर सामना करना पड़ा था। बेलारूस और रूस के खिलाफ अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा प्रतिबंधों के कारण हाल के महीनों में स्थिति और खराब हो गई है।

उन्होंने कहा है कि खाद्य तेल और दाल जैसी वस्तुओं के लिए भारत आयात पर निर्भर है, जिनकी वैश्विक कीमतें बहुत अधिक बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में हमारी सरकार अपने किसानों को लाभकारी मूल्य न देकर आयात–निर्भरता के साथ विकसित देशों को अधिक कीमत का भुगतान कर रही है।

किसान सभा नेताओं ने कहा है कि केंद्र सरकार ने खरीफ 2022–23 के लिए उत्पादन लागत का आकलन सी–2 +50% लागत की मांग को ठुकराकर मनमाना तरीके से किया है। यह किसानों के साथ धोखा है। उन्होंने कहा कि चूंकि देश के अधिकांश हिस्सों में कोई सरकारी खरीद नहीं है, इसलिए किसानों का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही इस मामूली एमएसपी का लाभ उठा पाएगा।

किसान सभा ने मांग की है कि सरकार स्वामीनाथन आयोग के सी2+50% के फार्मूले को गंभीरता से लागू करें, ताकि किसानों को उत्पादन की कुल लागत के 50 प्रतिशत रिटर्न का भुगतान किया जा सके। दलहन, तिलहन और बाजरा के लिए सार्वजनिक खरीद की व्यवस्था की जाए ताकि किसानों को इन फसलों को और अधिक उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इससे खाद्य मुद्रास्फीति को कम करने और देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

किसान सभा ने देश भर के किसानों से आह्वान किया है कि वे एमएसपी के वैधानिक अधिकार की मांग के लिए एक बार फिर से एकजुट होकर विरोध कार्यक्रम आयोजित करें। □

– सुरजीत सिन्हा

साझा मंच – ऐक्शन मोड में

जून माह की शुरुआती मीटिंग में ही तय हुआ कि साझा मंच के कार्यक्रम ऐक्शन आधारित होंगे। 10 जून को राँची के मेन रोड में जुलूस पर पुलिस द्वारा गोली चलाने से दो लोगों की मौत हुई, दसियों घायल हुए और अफ़वाहों के कारण शहर का माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया। प्रशासन ने पूरे शहर में धारा 144 लगा दिया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जुलूस में अल्प वयस्क और पच्चीस साल के कम उम्र वाले ही शामिल थे। जुलूसू पर अचानक से बिना किसी चेतावनी के पुलिस गोलियाँ चलाने लगी, दूसरी तरफ़ से पत्थरबाजी हुई, तीसरे तरफ़ से भी पत्थर बाज़ी हुई।

पुलिस–प्रशासन को पूर्व सूचना रहने के बाद भी जुलूस को नियंत्रित करने की कोई योजना नहीं थी, न वाटर केनन, ना शील्ड, सीधे फ़ाइरिंग! साझा मंच ने इस बर्बर पुलिस कार्रवाई की निंदा की। इसपर हस्तक्षेप करते हुए साझा मंच का एक प्रतिनिधिमंडल एसएसपी से मिला और उन्हें निर्दोषों को बिना किसी पुख्ता सबूत के नहीं तंग करने का अनुरोध किया जिसे मानते हुए उन्होंने थानों को आवश्यक निर्देश दिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मदद से हमारे सदस्यों ने आम जनता को आश्वस्त करते हुए किसी बहकावे में न आने का अनुरोध किया जिसका जनता पर व्यापक और सकारात्मक असर पड़ा। फ़ैक्ट–फ़ाइंडिंग कमिटी का गठन भी हुआ जो अभी भी काम में लगी है।

सांप्रदायिक–फासीवादी तत्व इस परिस्थिति का गलत फायदा न उठाएं, इसके लिए साझा मंच का ग्रुप सिख गुरुद्वारा कमिटी, मुस्लिम संस्थाओं, आर्च बिशप, बुद्धिस्ट सोसाइटी, जैन समाज और केंद्रीय सरना समिति से अलग–अलग मिला। सभी ने साझा मंच के पहल को सराहा और अपना सम्पूर्ण योगदान का भरोसा दिया। सभी जगह कुछ बिंदुओं पर पूरी सहमति बनी जैसे – साझा मंच को नफ़रत के ख़िलाफ सद्भाव और सौहार्द के इस मुहिम को लगातार लम्बे समय तक चलाना, नफ़रत के ख़िलाफ एकजुट हो कर प्रतिकार करना, अपने धर्म और समाज के लोगों को समझाना व शिक्षित करना, घर–समाज में युवकों से लगातार संवाद करना आदि।

अवल अल्ला नूर उपाया,
कुदरत के सब बंदे।
एक नूर से सब जग उपजा,
कवन भले को मंदे।।

कबीर के उक्त कथन से बगैर किसी भेद–भाव के मानवीय एकता का बोध होता है। सभी धर्मों के मूल में प्रेम, सेवा, करुणा, दया, न्याय की ही प्रधानता है, जिसे कोई भी धर्मावलंबी नकार नहीं सकता। यही सभी धर्मों का एक साझा संदेश है और साझी विरासत है जिसे आगे ले जाने के लिए साझा मंच कृतसंकल्प है।

चर्चा के दौरान ये बात आयी कि एक और साझी चीज़ है– हमारी नगरिकता। हम सब भारत के नागरिक हैं, हमारे सबके एक जैसे अधिकार व एक जैसे ही कर्तव्य हैं जो हमें देश के संविधान से मिला है। आज की सत्ता पर क़ाबिज़ फ़ासीवादी ताक़तें संविधान और संवैधानिक संस्थानों को लगातार कमजोर कर हमारे बुनियादी अधिकारों पर हमला कर रही हैं। हम भी अपनी बुनियादी नागरिक कर्तव्यों से लगातार चूक कर फ़ासीवादियों को मौक़ा दे रहे हैं।

हिंदुस्तान के पूरे इतिहास पर नजर डालें तो गणतंत्र होने के बाद हम पहली बार नागरिक होने का लाभ ले रहे हैं। इसे बचाए रखना है। कोई धर्म या धार्मिक ग्रंथ हमें सुरक्षा नहीं देता, सिर्फ़ संविधान ही हमें सुरक्षा प्रधान करता है। संविधान की रक्षा और प्रसार का एकमत से निर्णय हुआ।

25 जून 2022 को साझा मंच, झारखंड (समझ) की विस्तारित बैठक अंजुमन इस्लामिया, मेन रोड, राँची के हाल में प्रो. हरमिंदर बीर सिंह की अध्यक्षता में हुई जिसमें जुलाई में एकजुटता मार्च का और 6 अगस्त को कन्वेंशन का निर्णय हुआ। इस बीच रांची के सभी वार्डों और मुहल्लों एवं दूसरे ज़िलों में भी साझा मंच को ले जाने का निर्णय हुआ।

लगातार कार्यक्रम और सार्थक हस्तक्षेप के कारण समाज में साझा मंच की स्वीकार्यता बढ़ी है। □

नुपूर शर्मा ही एकमात्र दोषी

सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तल्ख टिप्पणी में नूपुर शर्मा के विवादास्पद बयान को देश की वर्तमान साम्प्रदायिक घटनाओं और तनावपूर्ण माहौल के लिए "एकमात्र दोषी" माना है और उसे राहत देने से इन्कार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उसे अन्य कोर्ट जाने का आदेश दिया है।

साझा मंच झारखंड ने भी नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल की अविलंब गिरफ्तारी की मांग के साथ एक ज्ञापन राज्यपाल को दिया है। □

राज्य स्तरीय जी बी मीटिंग

9 जून 2022 को स्थानीय एचआरडीसी हॉल में कॉ॰ जी॰ के॰ बक्शी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय जी॰ बी॰ मीटिंग हुई। मीटिंग में पोलिट ब्यूरो सदस्य कॉ॰ बृन्दा कारात ने 23वीं पार्टी कांग्रेस के राजनीतिक और सांगठनिक निर्णयों की रिपोर्टिंग की। उन्होंने कहा कि सिर्फ केन्द्रीय कमिटी के कार्यक्रमों पर निर्भर न होकर लोकल स्तर पर स्थानीय मुद्दों को चिन्हित करने के लिए जीवंत जन सम्पर्क बनाएं, और उसके आधार पर कार्यक्रम तय कर जनता की व्यापक भागीदारी से संगठन को मजबूती प्रदान करते हुए कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करें।

पोलिट ब्यूरो सदस्य कॉ॰ रामचन्द्र डोम ने पार्टी के डिजिटल बुलेटिन 'जन–जोहार' का उद्घाटन किया।

इससे पहले दोनों पोलिट ब्यूरो सदस्यों ने बिरसा मुण्डा की समाधि पर माल्यार्पण किया और मीटिंग के बाद प्रेस कान्फ्रेंस किया। □

क्यूं है ?

जो तू हर जगह, हर ज़र्रे में है,
तो यहाँ मंदिर औ मस्जिद क्यूँ है ?

जो तूने ही दी है बेख़ौफ़ ज़ुबान,
फिर मेरी आवाज़ पहरे में क्यूँ है?

जो तू ख़ुद को समदर्शी कहे,
तेरे जहाँ में अमीरी–ग़रीबी क्यूँ है?

जब समझा तुझे तो जाना,
तेरा होना 'उनके' लिए ज़रूरी क्यूँ है?

– अमल पांडेय

शिकायतकर्ता ही गिरफ्तार

सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी के खिलाफ राजभवन के समक्ष विरोध में वामदलों और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं की संयुक्त प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन सभा को संबोधित करते हुए माकपा के राज्य सचिव प्रकाश विप्लव ने कहा कि ज़किया जाफ़री के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का फ़ैसला आने के अगले ही दिन सामाजिक कार्यकर्त्ता तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ़्तारी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।

.... शेष पेज 4 पर

भारत का प्रथम ...

..... शेष पेज 1 का

कर दी जिससे कंपनी के अधिकारियों में इस विद्रोह से भय पैदा हो गया था।

इस जनयुद्ध ने अंग्रेजों को पानी पिला कर रख दिया था। ईस्ट इंडिया कम्पनी द्वारा घोषित 10,000 रुपए इनाम के लालच ने काम किया और अपनों में से ही किसी ने मुखबिरी करके सिदो–कान्हू को पकड़वा दिया। 26 जुलाई 1855 को भोगनाडीह गांव में ही पेड़ से लटका कर ईस्ट इंडिया कम्पनी ने उनकी हत्या कर दी। वहीं बहराइच में चाँद और भैरव को मार दिया गया। इस युद्ध में लगभग 20 हज़ार लोग मारे गए।

विडम्बना यह है कि जिन जमींदार, महाजन, पुलिस व सरकारी अमला गिरोह के नाश के लिए संताल हूल हुआ था, आज वही ताकतें 'हूल दिवस' मना रही हैं और सिदो–कान्हू–चांद–भैरव–फूलो–झानो के सपनों का समाज बनाने की बात कह रही हैं। क्या वास्तव में ये इनके सपनों का समाज बनाना चाहते हैं? क्या जंगलों की अंधाधुंध कटाई, पहाड़ों को पूंजीपतियों के पास बेचकर, आदिवासियों के जल–जंगल–जमीन को जबरन छीनकर, उन्हें लाखों की संख्या में विस्थापित कर अमर शहीद सिदो–कान्हू–चांद–भैरव–फूलो–झानो का सपना पूरा होगा?

आज सभी देशी–विदेशी पूंजीपतियों की गिद्ध दृष्टि झारखण्ड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्यप्रदेश जैसे प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्यों पर टिकी है। कॉरपोरेट और पूंजीपति भारतीय संसद और शीर्ष संवैधानिक संस्थाओं में घुसपैठ कर यहां के संसाधनों पर अवैध कब्जे की साजिशें रच कर आदिवासी समुदाय को संसाधनों से बेदखल करने में लगे हैं। 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती बदस्तूर जारी है। विकास परियोजनाओं के नाम पर आदिवासियों को सामुदायिक संसाधनों से बेदखल करना यह साबित करता है कि झारखण्ड के रूप में अबुआ राज तो मिल गया है लेकिन शासक और नीति निर्माता झारखण्ड वासियों के अबुआ राज के सपनों को कुचलने की हर संभव कोशिश में लगे हैं जिसके परिणाम स्वरूप असंतोष की ज्वाला अन्दर ही अन्दर सुलग रही हैं। यह कभी भी विद्रोह का रूप ले सकती है।

हूल दिवस की 167वीं वर्षगांठ पर ये सुनिश्चित करना होगा कि जल–जंगल –जमीन को पूंजिपतियों के पास बेचकर संताल हूल के शहीदों का सपना पूरा होगा या फिर जल जंगल जमीन को बचाने के लिए लड़ाई लड़ने वाले आदिवासियों के पक्ष में खड़े होकर? जिस तरह से सिदो–कान्हू को उनके ही कुछ लोगों ने दुश्मनों के हाथों पकड़वा दिया था, ठीक उसी तरह अपने जल–जंगल–जमीन को बचाने के लिए लड़ रहे आदिवाासियों को भी उनके ही कुछ तथाकथित अपने धोखा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी झारखंड के जंगलों से लेकर पश्चिम बंगाल, ओडिसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश आदि के जंगलों में उनका हूल जारी है और ये शोषण विहीन समाज की स्थापना तक जारी रहेगा।

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) संताल हूल के उद्देश्यों को पूर्ण करने में सभी शोषित वंचितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जनसंघर्ष में लगी हुई है। □

– अमल पाण्डेय

अग्निपथ ...

..... शेष पेज 1 का

लेकिन नियुक्ति 2% से भी कम लोगों की होती है और जो होती भी है वो गार्ड के रूप में, जिसमें उनके काम की शर्तें बदतर होती हैं।

सैन्य–सुरक्षा विशेषज्ञों का आकलन है कि अग्निवीर 6 महीने की ट्रेनिंग में विश्व स्तरीय सैनिक की तो छोड़िए, बिलकुल बुनियादी दक्षता भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। हथियारों पर ज़्यादा भरोसा आत्मघाती होगा। हथियार चलाने वाले हाथ, हौसला और प्रशिक्षण दक्षता ही युद्ध में निर्णायक होता है। अग्निपथ भर्ती स्कीम इस मामले में फिसड्डी है।

हिंदुत्व–कॉरपोरेट गठबंधन, अपने विरुद्ध पनप रहे आक्रोश को कुचलने के लिए, कट्टर निजी मिलिशिया के रूप में फ़ासीवाद के विस्तार के लिए इन रिटायर्ड अग्निवीरों का इस्तेमाल कर सकता है। भाजपा नेताओं के अनुसार रिटायर्ड अग्निवीरों को उनकी ऑफ़िस में गार्ड की नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी और उनके कॉरपोरेट आका सरकारी खर्च पर प्रशिक्षित अग्निवीरों को गार्ड, ड्राइवर, इलेक्ट्रिशियान, पलंबर आदि के रूप में भर्ती करेगी।

हर वर्ष औसतन 55 हज़ार सैनिक रिटायर होते हैं। पिछले दो वर्षों से सेना में भर्ती नहीं हुई और इस वर्ष भी सेना को जवान नहीं मिलेंगे अर्थात् 11 लाख की सेना में लगभग 15 प्रतिशत की कमी हो जाएगी। यह अपने को राष्ट्रवादी कहने वाली केंद्र सरकार की घोर लापरवाही है और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है।

अग्निपथ भर्ती स्कीम में "हक की जगह भीख" देख बेरोज़गार नौजवान इस क्रूर मज़ाक़ पर आग बबूला हो उठे और देश के चौदह राज्यों के साठ से ज़्यादा जिलों में उग्र प्रदर्शन किया और इससे क्षुब्ध दो नौजवानों ने आत्महत्या भी की।

रोज़गार, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, जनकल्याण, सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द जैसे सभी जनमुद्दों पर बुरी तरह से फेल और कॉरपोरेट–हितैषी सरकार को जन सरोकार से कोई मतलब नहीं है। रेलवे के साथ सेना में नियमित भर्ती ख़त्म करना और सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण, अस्थायी/ठेकेदारी पर निकृष्ट सेवा शर्तों पर नौकरी कराना ही इस क्षदम राष्ट्रवादी सरकार का चरित्र है जो अब खुल कर सामने आ गया है। अखिल भारतीय किसान सभा, डीवाईएफआई, एसएफआई की ज़िला इकाइयों ने 24 जून को पूरे राज्य में दो सौ से भी ज़्यादा स्थानों पर रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) स्थायी नियमित नौकरी के आकांक्षी करोड़ों बेरोज़गारों के आंदोलन के साथ है और सरकार से अग्निपथ भर्ती स्कीम को पूरी तरह से रद्द कर पुरानी सेवा शर्तों के साथ ही सेना में भर्ती की माँग करती है। साथ ही सैनिकों के 'एक रैंक एक पेंशन' के लंबित मांग को अविलम्ब लागू करने की भी मांग करती है। □

– समीर दास

संपादकीय

..... शेष पेज 1 का

चुकी है। दूसरी ओर यह कार्पोरेट परस्त सरकार राष्ट्रविरोधी 'अग्निपथ' जैसी विनाशकारी योजना लागू कर रही है जो हमारे देश के बेरोजगार युवाओं को भरी जवानी में गुलाम बनाने के साथ–साथ देश की सुरक्षा को कमजोर करने की योजना है। इस योजना के खिलाफ देश का संगठित युवा आंदोलन किसान आंदोलन की तरह एक लगातार और प्रभावी अभियान संगठित किए जाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

झारखण्ड में भी राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। राज्य में हेमन्त सोरेन की सरकार को गिराने के लिये बीजेपी–आजसू गठबंधन हर तरह के हथकंडे अपना रहा है। हाल ही में खनिज लीज के एक मामले को उठाकर बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राजनीतिक बढ़त लेने की कोशिश कर रही है। झारखण्ड में जिस तरह केन्द्र सरकार के इशारे पर ईडी और सीबीआई सक्रिय रूप से अपनी गतिविधियां चला रही है उसके पीछे अनियमितता और भ्रष्टाचार की जांच से ज्यादा भाजपा द्वारा सत्तारूढ़ दल पर दबाव बढ़ाना है ताकि वे भाजपा के समक्ष आत्मसमर्पण कर दें। पिछले विधानसभा सत्र में हेमन्त सरकार ने मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक बिल पारित किया था जिसे राज्यपाल की स्वीकृति के लिये भेजा गया लेकिन राजभवन ने इस बिल में कुछ त्रुटियां बताकर सरकार को वापस कर दिया है। इस बिल को पुनः ठीक कर वापस राज्यपाल के पास भेजने में हमेन्त सरकार देर कर रही है। इस प्रकार हेमन्त सरकार भी जनता के उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही है। राज्य में जनपक्षीय नीतियों को लागू किये जाने की दिशा में इस सरकार द्वारा कोई उल्लेखनीय कदम नहीं उठाए गए हैं। साथ ही इनके परिवार के अन्य सदस्य जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और राज्य सरकार की लोकप्रियता में गिरावट आ रही है जिसका लाभ लेने की कोशिश में भाजपा लगी हुई है। जेएमएम–कांग्रेस–राजद गठबंधन की सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार में बढ़ोत्तरी, कानून व्यवस्था की स्थिति में गिरावट और राज्य में बेरोजगार नौजवानों को काम दिये जाने की कोई ठोस योजना नहीं होने से इस सरकार के खिलाफ लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इस बीच 10 जून को रांची में हुई हिंसा में 2 लोगों की मौत और दर्जनों लोगों की घायल होने की घटना ने सभी अमन पसंद लोगों को चिंतित कर दिया है। हालांकि स्थिति अभी नियंत्रित है लेकिन पुलिस और प्रशासन की भूमिका संदेह के दायरे में है। संघ परिवार और भाजपा इस घटना पर साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण का संगठित प्रयास कर रही है लेकिन हेमन्त सोरेन की सरकार भी इस मामले में हस्तक्षेप के लिये राजनीतिक व प्रशासनिक निर्णय न लेकर पूरी तरह प्रशासन पर निर्भर हो गयी है। □

समृद्धि का असमान वितरण

विश्व असमानता रिपोर्ट, 2022 के अनुसार भारतीय आबादी के शीर्ष 10% के पास कुल राष्ट्रीय संपत्ति का 77% हिस्सा है। 2017 में सृजित संपत्ति का 73 फीसदी धन मात्र शीर्ष 1% अमीर के पास गया, जबकि 6.7 करोड़ भारतीयों, जिनमें सबसे गरीब आधी आबादी शामिल है, ने अपनी संपत्ति में केवल 1% की वृद्धि देखी। इसी रिपोर्ट में कहा गया की "भारत एक समृद्ध अभिजात्य वर्ग के बावजूद एक बहुत गरीब और असमान देश है", जहां प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक राष्ट्रीय आय 2021 में 2,04,200 रुपये और निम्न 50% की औसत आय मात्र 53,610 रुपये थी। शीर्ष 10% ने निम्न 50% से 20 गुना अधिक औसतन (11,66,520 रुपये) कमाए।

भारत में 119 अरबपति हैं। इनकी संख्या सन 2000 में केवल 9 थी, जो 2017 में बढ़कर 101 हो गई। 2018 और 2022 के बीच, भारत में हर दिन 70 नए करोड़पति पैदा होने का अनुमान है। पिछले एक दशक में अरबपतियों की संपत्ति में लगभग 10 गुणा वृद्धि हुई है और 2018–19 में तो उनकी कुल संपत्ति भारत के पूरे केंद्रीय बजट से भी अधिक है।

1991 में किए गए नवउदारवादी आर्थिक सुधारों का सीधा फायदा शीर्ष 1% आबादी को ही हुआ है और इसका सीधा नुकसान मध्यवर्गीय 40% और निम्नवर्गीय 50% को हुआ है। पिछले 31 वर्षों में आर्थिक सुधार के नाम पर किये जा रहे उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की नीतियों के अंधानुकरण से बड़े पैमाने पर सरकारी व सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण हुआ है, कॉरपोरेट्स को करों में ज़बरदस्त छूट और बैंकों की ज़बरदस्त लूट का मौक़ा मिला है, कॉरपोरेट्स का मुनाफ़ा बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर छँटनी, संविदा और ठेके पर नौकरी कराने आदि की सरकार से खुली छूट मिली है। मालिकों को श्रम क़ानूनों के खुले उल्लंघन की छूट रही है, अब तो सारे श्रम क़ानूनों को हटा कर मालिक/ कॉरपोरेट पक्षीय श्रम क़ानून लागू होने जा रहा है। नौकरी का स्वरूप बदल कर गुलामी का हो चुका है। हायर एंड फ़ायर, काम के घंटों में बढ़ोतरी, जॉब सिक्यूरिटी, पीएफ़, ग्रैच्यूटी, पेन्शन, आदि समाप्त हो चले हैं। कोविड की आपदा को अवसर में बदल कर करोड़ों रोज़गार छीन लिए गए हैं। लाखों सूक्ष्म और लघु उद्योग बंद हो गए हैं। ये जॉबलेस ग्रोथ और घटते वेतन–सुविधाओं का दौर है जहां 25 हज़ार

शेष पृष्ठ 4 पर .....

मातृ उद्योग .....

..... शेष पृष्ठ 1 का

सीएमडी न हो ! डूब जाए एचईसी! उल्लेखनीय है कि एचईसी से झारखंड सरकार को 2035 एकड़, स्मार्ट सिटी के लिए 675 एकड़, 1120 क्वार्टर, प्रोजेक्ट भवन, सचिवालय, इंजीनियरिंग होस्टल न0 1 एवं 2, एचएमटीपी बिल्डिंग, एफएफपी भवन का आधा पार्ट, एचएमबीपी इंजीनियरिंग बिल्डिंग, आर्टिजन हॉस्टल, रशियन होस्टल जिसमें विधान सभा और एमएलए निवास है आदि ले लिया है, बग़ैर किसी मुआवज़े के। एक पहल के तौर पर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने झारखंड सरकार को एचईसी का अधिग्रहण करने के लिए एक ज्ञापन दिया है।

कंपनी जब अपने शिखर पर थी, तब लगभग 22000 कर्मचारियों से भरपूर और एक आधुनिक टाउनशिप के साथ एचईसी भारत के सिरमौर उद्योगों में शुमार था। सरकारों की बदनीयती के चलते आज सिर्फ़ 1173 स्थायी और 1733 अस्थायी कर्मचारियों के साथ मरणासन्न स्थिति में है।

स्थिति ये है कि महाराष्ट्र के अभी के राज्यपाल कोश्यारी जी ने केंद्र सरकार को 2018 में 1100 करोड़ रूपये की लागत से एचईसी के आधुनिकीकरण की अनुशंसा की थी जो ठंडे बस्ते में है। राष्ट्रीय सुरक्षा और औद्योगिकरण की बुनियाद के बारे में उसे कोई चिंता नहीं है। प्रबंधन भी समय काट रहा है। ऐसे समय में बचे हुए मज़दूर ही एचईसी बचाने की मुहिम में लगे हैं। हटिया मज़दूर यूनियन (सीटू) के साथ मज़दूरों की तात्कालिक माँग है कि एचईसी का आधुनिकीकरण तुरंत किया जाय और कंपनी के पास उपलब्ध ज़मीन में से 58 एकड़ ज़मीन इच्छुक सरकारी /सार्वजनिक उपक्रमों यथा सीबीआई, इनकम टैक्स, तेनुघाट विद्युत निगम, एसआईबी, यूआईएडीआई, एफसीआई, ओएनजीसी, बीपीसीएल, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम को प्रति एकड़ 11.50 करोड़ रूपये के दर से 30 वर्ष की दीर्घकालीन लीज़ पर देने की अनुमति दी जाय ताकि वर्क ऑर्डर को पूरा करके कम्पनी को गति प्रदान की जाय।

आज जब मंदिरों का जीर्णोद्धार सरकार की प्राथमिकता है तो देश की धरोहर मातृ उद्योग के जीर्णोद्धार की ज़िम्मेवारी सिर्फ़ एचईसी के बचे मज़दूरों की नहीं हो सकती है, बल्कि हर नागरिक की है। एचईसी को बचाने और इसका जीर्णोद्धार अब जनमुद्दा है।

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) पूरी तरह से एचईसी बचाओ आंदोलन के साथ एकजुट है और इसे जनांदोलन बनाने में जुटी है। □

– भवन सिंह

शिकायतकर्ता .....

..... शेष पृष्ठ 2 का

2002 के गुजरात दंगों के पीड़ितों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ने के साथ कई दंगों में मारे गये सैकड़ों हिन्दुओं के लिये न्याय दिलाने में सक्रिय तीस्ता सीतलवाड़ को आश्चर्यजनक रूप से वादी को ही आरोपी मानकर गिरफ्तार कर लिया गया जो नैसर्गिक न्याय और मानवाधिकार के खिलाफ है। विरोध प्रदर्शन में तीस्ता की अविलंब रिहाई की मांग की गई। सभा को भाकपा (माले) के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्या, आदिवासी अधिकारों पर संघर्षरत दयामनी बारला और अन्य ने भी संबोधित किया। □

पाठकों की ओर से .....

अच्छी पहल, जन–जोहार के पाठकों की आवाज भी आगामी अंको में गूंजे। हम पाठकों के प्रश्नोत्तर का एक कॉलम जोड़ सकते हैं। –बिश्वजीत देब, जमशेदपुर

तस्वीरों में कार्यक्रम ...

जन जोहार का डिजिटल उद्घाटन

जोड़ापोखर थाना का घेराव

जामताड़ा में अग्निपथ पर पुतलादहन

बहरागोड़ा में अग्निपथ पर आंदोलन

भुरकुण्डा में कोयला खदानों के निजीकरण पर आंदोलन

सिन्दरी में अस्मित न्याय मंच द्वारा डिनोवली प्रिंसिपल का पुतला दहन

कोडरमा में प्रशासन के खिलाफ आमरण अनशन

जलेस देवघर का जिला सम्मेलन सम्पन्न

समृद्धि का असमान .....

..... शेष पृष्ठ 3 का

रूपये प्रतिमाह कमाने वाला भी देश के शीर्ष 10 प्रतिशत वेतन पाने वालों में शामिल है। वैश्वीकरण के दौर में आयात–निर्यात में मिली खुली छूट का पहले बिचौलियों ने और अब कॉरपोरेट ने पूरा फ़ायदा उठाया है। अनाज ख़रीद में सरकारी उदासीनता और एमएसपी बाध्यकारी ना होने का फ़ायदा उठाकर ये किसानों से औने–पौने दामों में जिन्स ख़रीदते हैं और ऊँचे दामों पर उनका निर्यात करते हैं। फिर इन्हीं जिन्सों की अपने ही देश में कमी हो जाती है तो ऊँचे दामों पर सरकार इन्हीं कॉरपोरेट के छद्म इकाइयों से इनका आयात करती है। लिहाज़ा बेतहाशा महंगाई बढ़ती है, किसान बर्बाद होकर क़र्ज़ के जाल में फँसते हैं व बिचौलिये/कॉरपोरेट मालामाल होते रहते हैं। किसान आत्महत्या करते हैं या किसानी छोड़ कर बेरोज़गारों की फ़ौज में शामिल होते जाते हैं।

सरकारी पैमाने के अनुसार 35 रूपये प्रतिदिन पाने वाला गरीब नहीं है। सकल राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा हिस्सा हड़पने वाले कॉरपोरेट और उनके पक्ष में षाष्टांग सरकार देश में विकराल असमानता का मुख्य कारण है और ये असमानता समाज में सभी स्तर पर तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, संस्थागत होती जा रही है। भारत दो देशों में बंट गया है। देश की 10 प्रतिशत आबादी कुछ भी ख़रीदने में या सारी उच्च सुविधाओं के उपभोग में सक्षम है तो बाक़ी 90 प्रतिशत, जिनमें महिलाएँ मुख्य रूप से प्रभावित हैं, रोज़मर्रा की ज़रूरतें जुटाने और निम्नस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य एवं नागरिक सुविधाओं पर जीने को अभिशप्त हैं।

पूँजी का इस स्तर पर मुट्ठी भर पूँजीपतियों में संघनन और फ़ासीवादी सत्ता को उनकी खुली मदद और दूसरी ओर तेजी से सर्वहारा बनता व्यापक समाज और आक्रोशित होता मज़दूर–किसान, फैलता जनांदोलन क्रांति की आहट सुनाते हैं। □ – प्रतीक

मांडर उपचुनाव

मांडर उपचुनाव में सीपीआइ (एम) ने पहली बार चुनाव लड़ा। संगठनात्मक और संसाधनों की कमी के बावजूद पार्टी ने लगभग 14 हजार वोट लाकर ठोस उपस्थिति दर्ज की है। □

पार्टी कोष में सहयोग की अपील

संघर्ष कोष के लिये स्वेच्छा से निम्नलिखित बैंक खाते में अपना योगदान करें।

Communist Party of India Marxist
Bank : Bank of Baroda
Main Branch, Ranchi
A/c No. : 00170200000219
IFSC Code : BARB0RANCHI

सीपीआई (एम) राज्य कमिटी, झारखण्ड की ओर से राज्य सचिव प्रकाश विप्लव द्वारा संपादित एवं प्रेषित। संकलन एवं संयोजन सुधांशु शेखर, अमल पाण्डेय व बिपिन कु0 सिन्हा।
अधिक जानकारी एवं सुझाव के लिये सम्पर्क करें– माकपा पार्टी कार्यालय, विश्वकर्मा मंदिर लेन, मेन रोड, रांची–834001, ई–मेल : janjohar.jharkhand@gmail.com